

दिनांक

हेमाशु कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

समाप्त

यमस्य जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्वाम्य एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-
उत्तर प्रदेश के विल्डर्सों द्वारा फ्लैट/भवन का पंजीयन नहीं कराये जाने के संबंध में।

लखनऊ, दिनांक: 17 मार्च, 2018

प्रति,

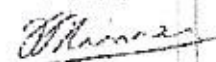
आप अवगत है कि प्रदेश में पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किये जाने तथा जन-सामान्य को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों तक जनता की सीधी पहुंच सुलभ कराये जाने हेतु प्रयत्न सतत प्रयत्नशील है।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि प्रदेश के कृत्तपय विल्डर्सों द्वारा फ्लैट/भवन के आवंटियों को कब्जा दे दिया गया है परन्तु उसका पंजीयन/निकषन नहीं कराया गया है, जिससे आवंटी विधिक विलेख के अभाव में परेशान है तथा इस संबंध में विल्डर्सों के विरुद्ध शिकायतें भी आ रही हैं। विल्डर्सों के इन कृत्य से आम जन मानस/आवंटी को असुविधा होने के साथ-साथ राज्य सरकार को भी अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रही है।

प्रश्नागत प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आम जन मानस एवं आवंटी के हित एवं अधिनियमों/नियमों/व्यवस्थाओं तथा विधिक प्रावधानों की शुचितता बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश के सभी विल्डर्सों से आवंटियों को आवंटी फ्लैट/भवन आदि का पंजीयन/निकषन कर्न अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि पंजीयन हेतु ऑन्लिन विकल्प के अभाव में प्रदेश के सभी जनपदों में जहाँ विल्डर्सों द्वारा आवंटी फ्लैट/भवन का पंजीयन/निकषन नहीं कराया गया है, वहां के विल्डर्सों को चेन्हित करते हुए जिलाधिकारीगण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 एवं उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्थापित और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम 2010 तथा भारतीय स्टाप अधिनियम 1899 में वर्णित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय



(हेमाशु कुमार)

प्रमुख सचिव।